

29.6.12. MANAMEDIA

नई दिल्ली, शुक्रवार 29 जून, 2012

किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने पर होगा विचार

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के जरिए सरकार किसानों को अधिक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि लाभकारी मूल्य दिलाने पर विचार करेगी। श्री

विचार कर रही है जिससे गन्ना किसान और चीनी उद्योग मिलकर प्रदेश की समृद्धि में योगदान दे सकें। श्री यादव ने कहा कि चीनी उत्पादन की बेहतर तकनीकी, गन्ने की पेराई से प्राप्त अपशिष्ट के पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) एगर्नल तथा

मिर्चों के जरिए ही अतिरिक्त बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार सभी संभव उपाय करेगी।

सरकार का प्रयास होगा कि इस अतिरिक्त बिजली उत्पादन से गांवों को अधिक और सुनिश्चित बिजली की आपूर्ति को जा सकें। उन्होंने किसान नेताओं द्वारा प्रस्तुत तीन ज्ञपत्रों में वर्णित सुझावों पर यह मसौदा दिया कि सरकार इनका परीक्षण कराकर हर मामले में किसान के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमण्डल में शामिल किसान नेताओं ने राज्य कृषि आयोग गठित करने, खेती में कारोबारी स्तर पर निवेश को बढ़ावा देने तथा बेहतर कृषि उत्पादन के लिए राज्य में बायो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कीटानुषों बीमारियों से बचाव, बेहतर फल सज्जिया और खाद्यान्न उगाने, भण्डारण के दौरान उत्पादों की लम्बे समय तक सुरक्षा करने, जलमय एवं जल अभाव वाले इलाकों के अनुरूप अधिक उत्पादन देने वाली लाभकारी फसलें उगाने, बीजों की गुणवत्ता और रोगमुक्तता सुनिश्चित करने तथा परिवहन के दौरान पोषक तत्वों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में सुझाव दिए।

■ मुख्यमंत्री ने कंसोर्टियम ऑफ इण्डियन फार्मर्स एसो. के प्रतिनिधिमण्डल को दिया आश्वासन
■ हर मामले में किसानों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी सरकार : अखिलेश

विद्युत उत्पादन के माध्यम से किसानों को बेहतर लाभ तथा इस क्षेत्र में नए रोजगारों के सृजन को संभावनाओं को भी मूर्तरूप दिया जाएगा।

इस क्षेत्र पर यदि पहले ध्यान दिया गया होता तो प्रदेश की अधिक समृद्धि और बढ़ती तथा राज्य की विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती। उन्होंने कहा कि अगले दो सालों के भीतर प्रदेश की चीनी



आधुनिक तकनीकों, बड़े पैमाने पर निवेश, कृषि उत्पादों की सुनियोजित मार्केटिंग तथा प्रबंधन के पर विभिन्न राज्यों के किसान संगठनों की शीर्ष में भी अधिक उदार नीतियों को अपनाने पर

बताया कि उनकी सरकार गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेगी। उन्होंने कहा कि अगले दो सालों के भीतर प्रदेश की चीनी